

ऋण मध्यस्थता - क्या विनियमन बाजार के साथ समझौता कर सकते हैं?*

एम. राजेश्वर राव

विशिष्ट अतिथियों, प्रोफेसरों और मेरे प्रिय छात्रों,

मुझे यहां आकर और इस सेमिनार में कुछ विचार साझा करते हुए खुशी हो रही है।

सेमिनार का विषय बैंकिंग विनियमन के दो प्रमुख उद्देश्यों - संस्थानों के लचीलेपन को बढ़ाना और प्रणालीगत स्थिरता को बनाए रखना - से बिल्कुल मेल खाता है। आज अपने संबोधन में, मैं उस पहलू के बारे में विस्तार से बात करना चाहूंगा जिसका बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है - प्रभावी और जोखिम रहित ऋण मध्यस्थता। एक ओर ऋण मध्यस्थता कुछ मायनों में अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली की भूमिका का वर्णन और परिभाषित करती है, वहीं दूसरी ओर, यह प्रभावी मौद्रिक संचरण और अर्थव्यवस्था के अधिक से अधिक वित्तीयकरण के लिए प्रमुख चैनल के रूप में भी कार्य करती है। हालांकि, यदि उचित रूप से विनियमित नहीं किया गया, तो यह चैनल संस्थानों को बर्बाद कर सकता है और व्यापक वित्तीय अस्थिरता का स्रोत बन सकता है। इसलिए, व्यवस्थित ऋण वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक विनियमन और वित्तीय मध्यस्थों की सुदृढ़ता आवश्यक शर्तें हैं। इसलिए, इसके लिए विवेकपूर्ण रूप से सुदृढ़ सीमाओं को डिजाइन करने में कुछ मुद्दे और चुनौतियाँ सामने आती हैं। इस संदर्भ में मैंने सोचा कि मैं सुदृढ़ ऋण बाजार की आवश्यकता और आगे की राह पर कुछ दृष्टिकोण साझा कर सकता हूँ।

I. वित्तीयकरण - हमारा क्या मतलब है और यह कैसे प्रासंगिक है?

सबसे पहले मैं अर्थव्यवस्था के वित्तीयकरण की गुंजाइश से शुरुआत करूंगा। जब भी हम वित्तीयकरण का उल्लेख करते हैं,

* आईआईएम कोझिकोड में बैंकिंग विनियमन, मध्यवर्ती सुदृढ़ता और प्रणालीगत स्थिरता पर उद्घाटन संगोष्ठी में 04 सितंबर, 2023 को श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर द्वारा दिया गया मुख्य भाषण। सौरभ प्रताप सिंह, पेशइमाम कबीर अहमद, प्रदीप कुमार और वैभव चतुर्वेदी द्वारा प्रदान किए गए बहुमूल्य इनपुट को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया जाता है।

तो लोकप्रिय बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ अर्थव्यवस्था के संचालन में वित्तीय बाजारों, वित्तीय कारकों और वित्तीय संस्थानों की बढ़ती भूमिका से समझा जाता है। आजादी के बाद से, हमारी अर्थव्यवस्था में काफी वृद्धि हुई है और हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति तक पहुंच गए हैं, जबकि हमने खुद को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार किया है। इस विकास पथ को अधिक उद्यमशीलता की भावना, नीति सुधार, संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन और संस्थागत संरचनाओं के विकास सहित कई कारकों द्वारा सक्षम और समर्थित किया गया है।

प्रभावी वित्तीयकरण इस यात्रा में एक प्रमुख प्रवर्तक रहा है। इसे संस्थागत आउटरीच, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और कई चैनलों पर बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता के संदर्भ में वित्तीय संस्थानों के प्रसार से सुविधा मिली है। देश भर में विस्तारित बैंक उपस्थिति, गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता में वृद्धि और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने तथा ऋण को लोकतांत्रिक बनाने के लिए अधिकारियों के सहवर्ती प्रयासों ने इस प्रक्रिया में सहायता की है। आपके द्वार बैंकिंग और बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट्स (बीसी) की अवधारणाओं ने वित्तीय समावेशन के विचार में क्रांति ला दी है और भारत में वित्तीयकरण को समग्र रूप से प्रसारित करने में मदद की है। हाल ही में, फिनटेक संस्थाओं के विकास और औपचारिक वित्तीय प्रणाली के साथ उनकी परस्पर क्रिया ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को जनता तक पहुंचाने के तरीके को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, परिवर्तनों ने इन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए मौजूदा और पारंपरिक दृष्टिकोणों का उपयोग करने में कई चुनौतियाँ भी सामने ला दी हैं, जो एक ऐसा मुद्दा है जिसका हल हमें नियामकों के रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता है।

II. ऋण वृद्धि - वित्तीयकरण और सुव्यवस्था की आवश्यकता में इसकी भूमिका

'क्रेडिट' शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्रेडेरे से हुई है जिसका अर्थ है 'सौंपना'। 'क्रेडिट' शब्द का वित्तीय उपयोग भी ट्रस्ट के उसी विचार को उधार लेता है जिसके तहत ट्रस्ट पर किसी व्यक्ति या इकाई को ब्याज के रूप में कुछ इनाम के साथ वापस पाने की उम्मीद के साथ पैसा दिया जाता है। बेशक, वित्तीय इकाई के लिए

यह भरोसा तुलन पत्र के दोनों तरफ रहता है। वित्तीय संस्थान, यथा बैंक, जनता से धन जुटाने में सक्षम हैं क्योंकि जनता अपनी जमा राशि रखने के लिए संस्थानों पर भरोसा करती है। साथ ही, जब ऐसी वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों को धन उधार देती हैं, तो उन्हें अपने उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता, इच्छा और क्षमताओं पर समान स्तर का भरोसा रखने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए, प्रणाली में धन-प्रवाह आपसी विश्वास पर आधारित है। वित्तीयकरण और इसकी सफलता का विचार विश्वास की इसी इमारत पर बनाया गया है।

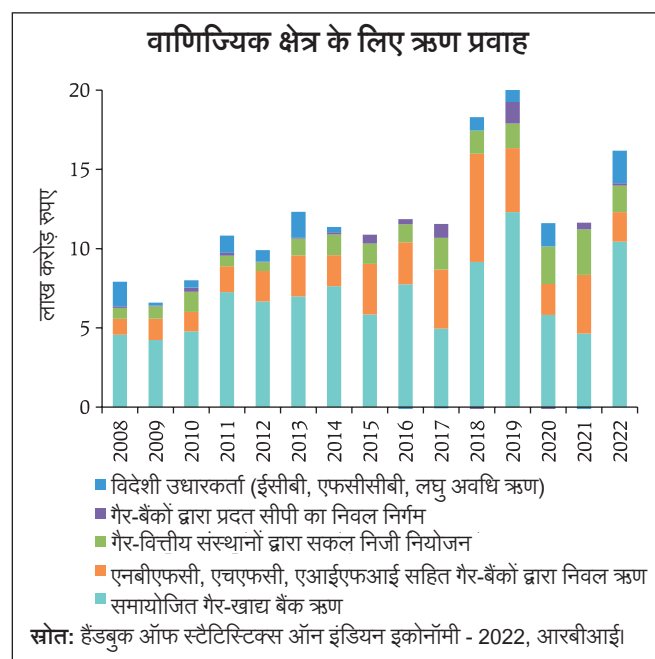
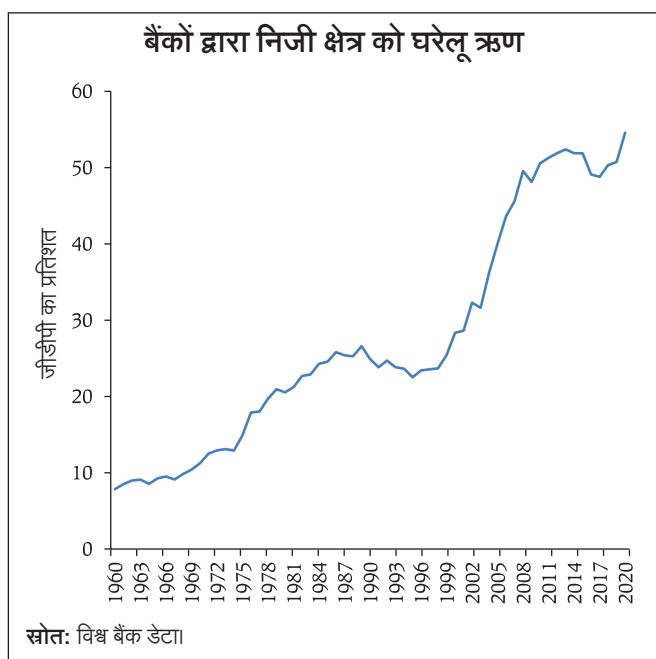
ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जो यह स्थापित करते हैं कि ऋण वित्तीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुभवजन्य रूप से भी, यह देखा गया है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह एक दूसरे के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं। समय के साथ, ऋण प्रवाह में वृद्धि ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि को भी पीछे छोड़ दिया है, जिससे अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र में पूंजी की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने में तेजी से योगदान हो रहा है। इस वृद्धि पर कुछ परिप्रेक्ष्य देने के लिए, यह कहना पर्याप्त होगा कि ऋण-से-जीडीपी अनुपात जो 1960 के दशक में लगभग 7-8 प्रतिशत के

बीच था, इस दशक की शुरुआत तक उल्लेखनीय रूप से बढ़कर लगभग 55 प्रतिशत हो गया है।

वित्तीयकरण के प्रभाव को स्वीकार करते हुए, मुझे इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि ऋण बाजार के बदलते घटकों का भारत में वित्तीयकरण पर व्यापक प्रभाव कैसे पड़ता है। वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों से युक्त ऋण का पारंपरिक रूप भारत के ऋण बाजारों पर हावी हो गया है, लेकिन हाल ही में ऋण साधनों के अन्य रूपों में भी वृद्धि हुई है। विशेष रूप से कॉर्पोरेट बॉण्ड, डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्रों जैसे बाजार से जुड़े लिखतों में ऊपर की ओर रुझान दिखाई दिया है।

आंकड़ों से संकेत मिलता है कि, यद्यपि बैंक अभी भी वाणिज्यिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा रखते हैं, उधार के अन्य स्रोत जैसे गैर-बैंकों से, या कॉर्पोरेट बांड और विदेशी उधार के माध्यम से भी बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई देती है।

एक तरह से, ये विकास पूरी तरह से जैविक नहीं हैं; वास्तव में, वित्तीय क्षेत्र को प्रसारित करने और ऋण के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कुछ नियामक संकेत दिए गए हैं। इससे यह सवाल उठता है कि यदि ऋण वृद्धि आधारित वित्तीयकरण अकेले ही आर्थिक विकास को गति दे सकता है, तो क्या हमें आर्थिक



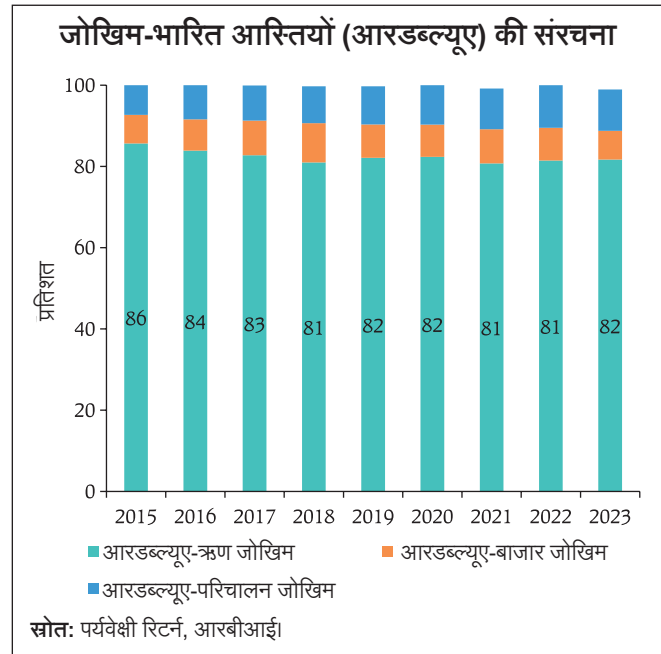
विकास के चालक के रूप में केवल ऋण वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए?

ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि अनियंत्रित और अनियमित तरीके से ऋण के अत्यधिक विस्तार के दो प्रमुख परिणाम हो सकते हैं - सबसे पहले, इससे वास्तविक क्षेत्र में अत्यधिक लीवरेज का निर्माण हो सकता है, और दूसरा, जैसा कि अक्सर अनुभव किया जाता है, अत्यधिक ऋण वृद्धि के प्रकरणों से ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा जोखिम अंकन के मानकों में कमी आ सकती है। इन दो कारकों के संयोजन से प्रणालीगत संकट पैदा हो सकता है और वित्तीय और प्रणालीगत स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा, इसका वित्तीय प्रणाली में 'विश्वास' के व्यापक पहलू पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हमने इसे 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान कठिन तरीके से सीखा है जब बेलगाम ऋण विस्तार के कारण बैंकिंग क्षेत्र में संकट उत्पन्न हुआ और बाद में यह एक प्रणालीगत संकट में बदल गया।

इसके अलावा, यदि अनियंत्रित ऋण वृद्धि की प्रक्रिया मौद्रिक अधिकारियों के आराम के स्तर से ऊपर धन की वृद्धि की ओर ले जाती है, तो धन आपूर्ति और मौद्रिक नीति आवेगों के संचरण को नियंत्रित करने के बारे में चिंताएं होंगी और मूल्य स्थिरता के व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए, यह केवल अयोग्य, बिना शर्त 'ऋण वृद्धि' नहीं है जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि 'व्यवस्थित ऋण वृद्धि' है जो प्रणाली में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखती है और इसके बदले में दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करती है।

ऋण बाजार के नियमन की आवश्यकता

वित्तीय संस्थानों के ऋण पोर्टफोलियो के आकार और उनके तुलन पत्र में ऋण जोखिम की बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए, यह जरूरी है कि संस्थान की वित्तीय सुदृढ़ता और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने की किसी भी रणनीति में 'ऋण जोखिम' को अपने मूल तत्व के रूप में माना जाना चाहिए।



यदि हम ऋण जोखिम के परिदृश्य में थोड़ा गहराई से उतरें, तो स्पष्ट रूप से हमें तीन मूलभूत तत्व अर्थात् - 'विश्वास', 'विवेक' और 'संविदा संबंधी व्यवस्थाएं' जो परस्पर अंतर-संबंधी भी हैं, जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। उचित संविदात्मक व्यवस्था होने के बावजूद सूचना विषमता के परिणामस्वरूप कमजोरियाँ हो सकती हैं जो संभावित रूप से ऋण मध्यस्थता की प्रक्रिया को बाधित कर सकती हैं। नियामकीय ढाँचे और नीतियाँ यहाँ चलन में आती हैं और हमारी नियामक नीतियों को इस विश्वास की कमी को दूर करने या किसी न किसी तरीके से इसकी भरपाई करने के लिए ऋण मूल्यांकन, उचित सावधानी, वसूली और समाधान से संबंधित सुविचारित ढाँचे की आवश्यकता होती है। नीतियाँ यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि उधार व्यवसाय से जुड़े जोखिमों को विवेकपूर्ण ढंग से मापा, प्रबंधित और निर्धारण किया जाए।

इस विषयगत सेमिनार के परिप्रेक्ष्य से, मुझे ऋण जोखिम प्रबंधन के 'विवेकपूर्ण' पहलू पर ध्यान केंद्रित करने दें, जिसके लिए हमारे पास एक सिद्धांत-आधारित नियामक दृष्टिकोण है। हमारे दृष्टिकोण को आकर्षक तरीके से वर्णित करने के लिए, हम इसे जोखिम प्रबंधन के लिए 5M ढांचा कह सकते हैं जो निम्नलिखित पांच तत्वों पर केंद्रित है - मापन (मेजरमेंट),

निगरानी (मॉनिटरिंग), प्रबंधन (मैनेजमेंट), अल्पीकरण (मिटिगेशन) और स्थानांतरण (माइग्रेशन)। इस ढांचे के अवयव परस्पर अनन्य नहीं हैं और एक-दूसरे के साथ परस्पर कार्य करते हैं, जुड़े होते हैं और एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।

इसकी व्याख्या देखते हैं:

- **मापन (मेजरमेंट):** प्रसिद्ध प्रबंधन विशेषज्ञ पीटर ड्रकर ने एक बार कहा था कि "यदि आप इसे माप नहीं सकते, तो आप इसे प्रबंधित नहीं कर सकते"। मेरा मानना है कि यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, और जोखिम प्रबंधन से संबंधित बैंकिंग नियम भी इसी दृष्टिकोण का पालन करते हैं। ऋण जोखिम को मापने के लिए, रिजर्व बैंक सहित दुनिया भर के सभी नियामकों ने जोखिम के उचित माप को स्थापित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।
- **निगरानी (मॉनिटरिंग):** ऋण जोखिम प्रबंधन का यह पहलू काफी हद तक वित्तीय संस्थानों द्वारा उनकी नीतियों के माध्यम से की जाने वाली निगरानी और निरीक्षण पर निर्भर करता है जिसे नियामकों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। संबंधित वित्तीय संस्थानों को जोखिम प्रबंधन, प्रशासन, अनुपालन आदि पर विवेकपूर्ण नीतियां बनाने का आदेश दिया गया है। इन मानदंडों का उद्देश्य प्रणाली में किसी भी अंतर्निहित नैतिक खतरे को दूर करना है। आमतौर पर संस्थानों के लिए आंतरिक जांच की तीन परतें निर्धारित होती हैं- पहला, ऋण की उत्पत्ति के समय जोखिम अंकन और उचित सावधानी, दूसरा, आंतरिक जोखिम प्रबंधन और अनुपालन प्रथाओं का पालन, और तीसरा, आंतरिक लेखा परीक्षा। इसकी जांच पर्यवेक्षी निरीक्षण के हिस्से के रूप में की जाती है, जिसमें इन मापदंडों पर वित्तीय संस्थानों के प्रयासों का आकलन करने के अलावा, पर्यवेक्षक यह भी आकलन करते हैं कि क्या बैंक द्वारा बनाए गए सामान्य या अन्य प्रावधान वास्तव में अंतर्निहित जोखिम को दर्शाते हैं।
- **प्रबंधन (मैनेजमेंट):** जोखिम-और-इनाम अदायगी को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय संस्थान अपने जोखिम

प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में कुछ जोखिम उठाना और प्रबंधित करना पसंद कर सकते हैं। वह मूलतः एक व्यावसायिक निर्णय होगी। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनियमित संस्थाओं को उनके जोखिम के अनुपात में अच्छी तरह से पूंजीकृत किया गया है, दुनिया भर के नियामक पूंजी पर्याप्तता मानदंड निर्धारित करते हैं जहां कुछ सिद्धांतों के आधार पर बैंकों द्वारा न्यूनतम नियामक पूंजी प्रदान की जाती है। यह तब जोखिम प्रबंधन का पहला स्तर बन जाता है जिसमें जोखिम को आंतरिक रूप से अवशोषित किया जाता है, और उसके लिए पर्याप्त पूंजी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, ऋण का मूल्य निर्धारण भी इस जोखिम रिटर्न ट्रेड-ऑफ को प्रभावित करता है।

- **अल्पीकरण (मिटिगेशन) :** यदि वित्तीय संस्थान द्वारा उठाया गया जोखिम उसके सुविधा क्षेत्र ("जोखिम भूख") से आगे बढ़ जाता है, तो उन्हें इसे केवल अवशोषित करने के बजाय सक्रिय रूप से प्रबंधित करना पड़ सकता है। यह जोखिम अल्पीकरण दो स्तरों पर लागू किया जाता है - पहला नियामकों द्वारा - जो प्रावधानीकरण मानदंडों या जोखिम सीमाओं की तरह प्रकृति में अधिकतर विवेकपूर्ण होता है। दूसरा संस्थागत स्तर पर, जिसमें संस्थान स्वयं एकाग्रता जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए जोखिम सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं या उधारकर्ताओं पर कुछ संपार्श्विक बाधाएं डाल सकते हैं या जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए कठोर अनुबंध निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा, वित्तीय संस्थान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनुमत ऋण जोखिम अल्पीकरण उपायों जैसे ऋण गारंटी, संपार्श्विक लेनदेन, तुलन पत्र निवल निधि निर्धारण आदि को भी लागू कर सकते हैं।
- **स्थानांतरण (माइग्रेशन) :** इसमें बैंक की पुस्तकों से जोखिम को बाहर निकालना शामिल है। ऋण जोखिम के हस्तांतरण या स्थानांतरण के लिए कई लिखत उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन मैं उनमें से दो पर बात करने जा रहा हूँ। पहला और शायद सबसे लोकप्रिय

तरीका आस्ति (ऋण) और संबंधित जोखिम को किसी अन्य इकाई को स्थानांतरित करना है। इस पद्धति में, संबंधित वित्तीय संस्थान द्विपक्षीय व्यवस्था या अन्यथा के माध्यम से एक इच्छुक पात्र पार्टि को एकल ऋण या ऋणों का पूल हस्तांतरित करना पसंद कर सकता है। आर्थिक जोखिम अंतरणकर्ता की पुस्तकों से अंतरिती को हस्तांतरित हो जाता है। दूसरा विकल्प प्रतिभूतिकरण का है। इस व्यवस्था में, ऋणों का प्रवर्तक ऋणों के एक पूल का चयन करता है और इसे एक विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) में स्थानांतरित करता है जो ऋणों को सुरक्षित करता है और निवेशकों के एक विविध समूह को प्रतिभूतिकरण नोट बेचता है। यह विधि प्रणाली में ऋण जोखिम की प्रकृति और एकाग्रता में विविधता लाती है।

अधिकांश ऋण जोखिम प्रबंधन लिखतों के मामले में, विशेष रूप से ऋण जोखिम हस्तांतरण या स्थानांतरण के मामले में, बाजारों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यदि संबंधित ऋणदाता अपने जोखिम को स्थानांतरित करना पसंद करता है, तो उसे हमेशा एक प्रसारित और जीवंत बाजार की आवश्यकता होगी जिसमें वह अपने जोखिम को बेच सके। एसपीवी के माध्यम से जोखिमों के साथ-साथ आर्थिक हितों को स्थानांतरित करने या आस्तियों को सुरक्षित करने के लिए लेनदेन के दूसरी तरफ संस्थानों के व्यापक आधार की भागीदारी की आवश्यकता होती है। एक प्रसारित बाजार न केवल इस लेनदेन को सुचारु रूप से सुविधाजनक बनाएगा, बल्कि ऐसी आस्तियों के उचित मूल्य निर्धारण में भी सहायता करेगा। इसलिए, एक इकाई से दूसरी इकाई में ऋण जोखिम के सुचारु स्थानांतरण की सुविधा के लिए बाजार सक्षम ढांचे का विकास करना रिजर्व बैंक का मुख्य क्षेत्र रहा है। मैं इस संबंध में की गई कुछ पहलों पर संक्षेप में बात करना चाहूंगा।

III. हाल की पहल और आगे का रास्ता:

हालांकि ऊपर वर्णित ऋण जोखिम प्रबंधन के तरीके संपूर्ण नहीं होंगे, वे मोटे तौर पर भारत और विश्व में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं। रिजर्व बैंक इन विषयों पर हमारी विनियमित संस्थाओं के लिए सक्षम ढांचा प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। ऋण जोखिम के प्रबंधन और अल्पीकरण से संबंधित नियम पहले से ही काफी मजबूत हैं

और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हालांकि, हमारी हालिया नियामक पहलों के एक हिस्से के रूप में, हम स्थानांतरण या ऋण जोखिम के हस्तांतरण के तंत्र में सुधार के लिए नीतिगत उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

सितंबर 2021 में, हम ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण और मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए दिशानिर्देशों का एक संशोधित सेट लेकर आए। इन रूपरेखाओं को बाजार की अपेक्षाओं को शामिल करने के लिए एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद विकसित किया गया था और इन नीतिगत उपायों को वैश्विक मानकों के साथ जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रणाली में ऋण जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सके। चूंकि हमें यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि इस तरह की महत्वपूर्ण पहल अपने डिजाइन में लचीली हों, हमने नियमित अंतराल पर इन रूपरेखाओं की समीक्षा करने, बाजार की प्रतिक्रिया और विभिन्न प्रतिभागियों की टिप्पणियों को आत्मसात करने के लिए एक आंतरिक तंत्र भी स्थापित किया है।

इसी प्रकार, प्रतिभागी आधार का विस्तार करके सीडीएस के लिए बाजार के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, ऋण चूक स्वेप (सीडीएस) पर दिशानिर्देश को 2022 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। बैंकों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के अलावा, उक्त नियम सभी प्रमुख गैर-बैंक विनियमित संस्थाओं द्वारा सीडीएस के माध्यम से संरक्षण बेचने की अनुमति देते हैं।

यहां इस बात पर जोर देना उचित है कि जबकि ऋण हस्तांतरण और प्रतिभूतिकरण पर हमारे दिशानिर्देश सामान्य रूप से ऋण को कवर करते हैं, सीडीएस दिशानिर्देश मुद्रा बाजार लिखतों और कुछ कॉरपोरेट बॉण्डों को कवर करते हैं। यह इसे दो अलग-अलग और महत्वपूर्ण ऋण लिखतों - ऋण और कॉरपोरेट बॉण्ड के लिए जोखिम प्रबंधन का एक पूरक लिखत बनाता है।

मुझे आगे के संभावित रास्ते पर कुछ दृष्टिकोण भी साझा करने दीजिए। भविष्य का ऋण बाजार इस समय की तुलना में अधिक तेज होने की संभावना है। हमें ऋण लिखतों के लिए एक गतिशील द्वितीयक बाजार, बाजार में प्रतिभागियों और आस्ति वर्गों का एक व्यापक आधार और जोखिम मूल्यांकन के लिए एक मजबूत ढांचे की भी आवश्यकता होगी। इन समर्थकों के आधार पर, विभिन्न भागीदारों के बीच सहज संप्रेषण सुनिश्चित करना और वित्तीय संस्थाओं को उनके तुलन पत्र को जोखिम से मुक्त करने के अवसर प्रदान करना संभव हो सकता है।

एक सक्रिय द्वितीयक ऋण बाजार का विकास

एक कुशल बाजार वित्तीय प्रणाली में मतभेदों को भी कम करता है। सुचारु ऋण प्रवाह और मजबूत जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवस्थित तरीके से बाजार का विकास आवश्यक है। ऋणों के व्यापार के लिए ऋण बाजार विकसित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 2020 में एक द्वितीयक ऋण बाजार संघ (एसएलएमए) के गठन की सुविधा प्रदान की। एसएलएमए प्लेटफॉर्म, जो 2022 में चालू हुआ, कई प्रमुख बैंकों से जुड़ गया है और एनबीएफसी सहित अन्य प्रमुख प्रतिभागियों को शामिल करने की प्रक्रिया में है। इस प्लेटफॉर्म का मूल विचार बाजार-आधारित नीलामी तंत्र के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण के आसान हस्तांतरण को सक्षम करना है, जहां द्विपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से ऋण बेचने के बजाय सभी इच्छुक पार्टियों से उद्धरण प्राप्त किए जाते हैं। एक प्रसारित और सक्रिय द्वितीयक बाजार, जिसे एसएलएमए के माध्यम से विकसित करने की परिकल्पना की गई है, बाजार सहभागियों के बीच ऋण और ऋण जोखिम के हस्तांतरण में निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

ऋण बाजारों में प्रतिभागियों के प्रकार का विस्तार करना

परंपरागत रूप से, भारत में ऋण बाजार को सख्ती से विनियमित किया गया है, जो मुख्य रूप से बैंकिंग और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता से प्रेरित है। हालाँकि, यह स्वीकार किया गया है कि बाजार में प्रतिभागियों के विविध समूह को अनुमति देने से वास्तव में इसे अधिक जीवंत और कुशल बनने में मदद मिल सकती है। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने हमारे नियामकीय दायरे से बाहर, लेकिन अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा विनियमित संस्थाओं को ऋण जोखिम ढांचे के हस्तांतरण के तहत दबावग्रस्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देकर ऋण बाजारों को उदार बनाने के लिए पहला कदम उठाया। इसी तरह, मानक आस्तियों के लिए, प्रतिभूतिकरण ढांचा निवेशकों के विभिन्न समूहों को अंतर्निहित ऋणों के प्रतिभूतिकरण नोट्स की सदस्यता लेने की अनुमति देता है। प्रतिभागियों का व्यापक समूह होने से, यह परिकल्पना की गई है कि ऋण बाजार अधिक जीवंत, प्रभावी और पारदर्शी हो जाएंगे।

वर्तमान में प्रतिबंधित आस्ति वर्गों के प्रतिभूतिकरण की अनुमति देना

भारत में प्रतिभूतिकरण उत्पादों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में इसके कई गुना बढ़ने की संभावना है। 2021 में जारी प्रतिभूतिकरण पर हमारी रूपरेखा में कुछ आस्ति वर्गों को प्रतिभूतिकरण से प्रतिबंधित करने वाली एक नकारात्मक सूची है। लेकिन यह कोई निश्चित बहिष्करण नहीं है। हम बाजार की वृद्धि और परिपक्वता पर लगातार नजर रखते हैं और यदि वर्तमान परिस्थितियों में कुछ प्रतिबंधित आस्तियों को प्रतिभूतित किया जा सकता है तो हम एक अच्छी तरह से विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हैं।

निष्कर्ष

संक्षेप में कहें तो, जबकि वित्तीयकरण के नजरिए से अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए ऋण एक महत्वपूर्ण चालक है, हमें ऋण जोखिम को प्रबंधित करने के लिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचे की आवश्यकता है। ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए लिखतों की शृंखला विनियामकीय अंतिम सीमा प्रदान करने वाली विवेकपूर्ण सीमाओं के साथ विकसित हुई है। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संस्थाओं के बीच ऋण जोखिमों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए मजबूत ऋण बाजार विकसित करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक द्वारा कई नीति प्रवर्तक स्थापित किए गए हैं।

जैसा कि आपने देखा होगा, 'जोखिम' की चर्चा आज मेरे विचार-विमर्श के मूल में थी। एक नियामक के रूप में, हम स्वीकार करते हैं कि जोखिम को टाला नहीं जा सकता। आखिरकार, जोखिम-और-इनाम की गतिशीलता वित्त की संपूर्ण इमारत की आत्मा है! कवि विलियम आर्थर वार्ड की एक प्रसिद्ध कविता "जोखिम (रिस्क)" की कुछ पंक्तियाँ याद करना उचित होगा-

.... आशा करना निराशा का जोखिम उठाना है,
प्रयास करना असफलता का जोखिम उठाना है।

लेकिन जोखिम तो लेना ही चाहिए क्योंकि
जीवन में सबसे बड़ा खतरा कोई जोखिम न उठाना है...

इसलिए, कुछ जोखिम तो उठाए ही जाने चाहिए। हालाँकि, यह हमारे सामूहिक हित में है कि हम जो जोखिम उठा रहे हैं उसे जानें, उसका पर्याप्त रूप से आकलन करें और उसे प्रबंधित करने की क्षमता हासिल करें।

आप सभी को धन्यवाद।